'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.08.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज ;राम राजद्ध चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 19 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 अगस्त, 2016

निजी क्षेत्र में आरक्षण देना समय की मांग : डॉ. उदित राज

अनुसूचित जाति आयोग एवं सफाई आयोग का गठन करे हरियाणा सरकार

चंडीगढ़, 27–28 अगस्त, 2016. अजा/जजा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज ने कहा है कि वर्तमान परिवेश में सरकारी क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने लोकसभा में प्राइवेट सदस्य बिल प्रतिस्थापित किया है। डॉ. उदित राज शनिवार को यहां लॉ ऑडोटोरियम में परिसंघ की हरियाणा इकाई द्वारा शुरू किए गए दो दिवसीय मंथन शिविर का उदघाटन करने के बाद हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए हुए कर्मचारी नेताओं, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।

तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए डॉ. उदित राज, सत्य प्रकाश जरावता एवं महासिंह भूरानिया

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही है। जिसे अमली रूप देने के लिए उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से देशभर में दलितों व पिछड़ा वर्ग के लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया है। इस दिशा में हरियाणा के दलित एवं पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों को दो दिन तक मंथन शिविर के माध्यम से जागरूक किया जाएगा।

हरियाणा में होने वाली दलित उत्पीडऩ की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. उदित राज ने कहा कि हरियाणा सरकार को बिना किसी देरी के स्थाई अनुसूचित जाति आयोग का गठन करना चाहिए। यह दलितों की जरूरत है। हरियाणा सरकार द्वारा बोर्ड, निगमों तथा अन्य संस्थानों में दलितों को दिए गए प्रतिनिधत्व पर असंतुष्टता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार दलितों को उनकी संख्या के आधार पर नुमांइदगी प्रदान करे।

इससे पहले डॉ. उदित राज का यहां पहुंचने पर स्वागत करते हुए परिसंघ की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि दो दिवसीय शिविर के दौरान हरियाणा प्रदेश में दलितों की समस्याओं तथा दलितों की स्थिति पर मंथन किया जाएगा।

दो दिवसीय मंथन शिविर के दौरान प्रस्ताव पारित करके हरियाणा सरकार से सफाई आयोग का गठन किए जाने की मांग की है। सफाई आयोग के माध्यम से ही हरियाणा के विभिन्न विभागों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए।

मंथन शिविर के समापन अवसर पर पारित किए गए प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते हुए परिसंघ की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम दिए गए ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का बैकलॉग पूरा करने, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों व अधिकारियों को पदोन्नति में तरक्की का लाभ देने, सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा बंद करने, भूमिहीन खेतीहीन मजदूरों का हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड में पंजीकरण करवाने, हुडा व एचएसआईआईडीसी के प्लाटों में आरक्षण लागू करने, हरियाणा विद्यालय बोर्ड के प्रत्येक जिले में समन्वय केंद्र खोलने तथा बोर्ड, निगमों व अन्य संस्थानों में दलितों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है। इस अवसर पर परिसंघ के विश्वनाथ सिंह, शशीकांत, रामपाल पाली, महा सिंह भूरानिया समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

चंडीगढ़ में परिसंघ के दो दिवसीय सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह का एक दृश्य

धौलपुर में राजस्थान परिसंघ का सम्मेलन संपन्न

अनुसूचित जाति / जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज परिसंघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जो सचिन पैलेस, बाड़ी में आयोजित था, में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण, दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी सांसद, विधायक या क्षेत्रीय नेताओं की ही नहीं हैं बल्कि आरक्षण का लाभ ले रहे सरकारी नौकरी वाले अधिकारियों, कर्मचारियों की भी हैं जब तक यह दोनो मिलकर काम नहीं करेगें तब तक दलित समस्याओं का हल नहीं होगा। डॉ. साहब ने कहा कि नेताओं को राजनीतिक दल टिकट देकर सांसद व विधायक बनाते हैं, वह आरक्षण के लिए कुछ बोलते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। इसका विरोध करने के बजाय हमारा ही कोई व्यक्ति उसका स्थान लेने को तैयार हो जाता है। आरक्षण का लाभ ले रहे अधिकारी–कर्मचारी मूकदर्शक बने रहते हैं। अगर सभी लोग मिलकर विरोध करें तो राजनैतिक पार्टियां सोचने को मजबूर हो जाएं। निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि निजी खेत्र में आरक्षण का मामला लटक गया है। अब यह आसानी से मिलने वाला नहीं है। दलित उत्पीड़न पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समय तेजी से बदल रहा है। अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करें। अगर सोसल मीडिया न होता तो पूना की घटना दब जाती। देश का दलित वर्ग जाति व्यवस्था खत्म करना चाहता है लेकिन इसके लिए पहल सवर्ण वर्ग को करनी होगी। देश में जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा।

बाड़ी में सम्मेलन को संबोधित करने से पहले उदित राज जी का बरैठा पर परिसंघ तथा दलित वर्ग के लागों ने उनका फूल–माला पहनाकर स्वागत किया गया। बरैठा पर स्वागत करने के लिए संयोजक – सदस्यता रथ राजस्थान रनजीत मीणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष – दलित सेवा संघ बुद्धिराम लहरी, राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजवीर मीणा, खटीक समाज के जिलाध्यक्ष इन्द्रजीत नागर, परिसंघ के दौसा जिलाध्यक्ष सोहन लाल आदि लोग कार्यकर्त्ताओं के साथ पहुंचे।

इसके बाद डॉ. उदित राज जी ने सागरपाड़ा स्थित अम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

सर्किट हाउस धौलपुर में प्रेस काफ्रेंस करते हुए परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं यहां एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आया हूं न कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में आया हूं। परिसंघ पदोन्नति में आरक्षण तथा दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल मैंने संसद में पेश कर दिया है, इसके लिए हमें सभी सांसदों के सहयोग की जरूरत है। न्यायपालिका के सहारे सवर्ण हमारे आरक्षण के खिलाफ साजिस कर रहे हैं। परिसंघ की सदस्यता विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि रंजीत मीणा के निर्देशन में संपूर्ण राजस्थान में सदस्यता रथ द्वारा परिसंघ की सदस्यता विस्तार पर जोर दिया जाएगा। अपने लोगों को जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है।

कर्मचारियों के सहयोग से उनकी शक्ति के बल पर पार्टी खड़ी करने का अभिनव प्रयोग या तो मान्यवर कांशीराम ने किया है या ये कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है।

सर्किट हाउस, धौलपुर से ही उन्होंने परिसंघ की सदस्यता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समय संयोजक सदस्यता रथ राजस्थान व परिसंघ के जिलाध्यक्ष रनजीत मीणा साथ थे। बुद्धिराम लहरी, इन्द्रजीत नागर, देवेन्द्र प्रताप मीणा, विजय लहरी, बबलू उमरेह, सोनू उमरेह आदि उपस्थित थे।

प्रदेश स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता आदिवासी मीणा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया ने की। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में दलित व आदिवासी एक हो गए तो किसी में हिम्मत नहीं कि दलित व आदिवासियों का कोई उत्पीड़न कर सके। उन्होंने राजस्थान में उपजे अनावश्यक मीणा–मीना विवाद को लेकर कहा कि महासभा ने दीपपुरा में आंदोलन किया था। राजस्थान सरकार मीणा–मीना मुद्दे का स्थायी हल निकाले। उन्होंने डॉ. उदित राज जी की प्रशंसा करते हुए कि कि उदित राज जी जैसा संघर्षशील नेता देश में होना बहुत जरूरी है वरना हमारा ऐसे ही उत्पीड़न होता रहेगा। बसेड़ी से विधायक रानी सिलोटिया ने कहा कि मैं दलित समाज के साथ खड़ी हूं। मैं सरकार के सामने समाज का पक्ष रखूंगीं। पूर्व विधायक बसेड़ी सुखराम कोली ने कहा कि डॉ. उदित राज का जीवन सम्मान के लिए समर्पित रहा है। हम उदित राज जी के साथ खड़े हैं। देवी सिंह राणा राष्ट्रीय अध्यक्ष, एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि समाज में बिखराव नहीं होना चाहिए क्योंकि बिखराव की स्थिति में बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठाते हैं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए परिसंघ के जिलाध्यक्ष व संयोजक सदस्यता रथ रनजीत मीणा ने कहा कि मैं बहुत आभारी हूं कि डॉ. उदित राज जैसा बड़ा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में हैं। हम इनके नेतृत्व का फायदा समाज को देना चाहते हैं। मैं आभारी हूं यहां उपस्थिति सभी व्यक्तियों का जिन्होंने यहां अपनी भागीदारी निभाकर दलित वर्ग की आवाज को बुलंद करने का कार्य किया है। राजवीर मीणा ने कहा कि महासभा के सभी छात्र परिसंघ के साथ खड़े हैं। कार्यक्रम को पार्षद राधारमन राघव, श्यामबाबू रावत, नत्थीलाल पहाड़िया, बुद्धिराम लहरी, देवेन्द्र मीणा, हेतराम नागर, राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के प्राचार्य रमेश नसवारिया, आर.ए.एस. सत्येद्र मीणा, ज्वान सिंह, मोहर सिंह मीणा, मोहर सिंह, पप्पू सोनी, राजन, जगदीश पहाड़िया, राम भजन मीणा (जिलाध्यक्ष), आदिवासी मीणा समाज, उपप्राचार्य, पी.जी. कॉलेज धौलपुर मनरूप मीणा आदि ने मंच को संबोधित किया।

कार्यक्रम में राम लखन मीणा, हरी सिंह सरपंच उमरेह, मूंगा, भत्ता सरपंच तथा सहोड़ी के पूर्व सरपंच तथा सहेड़ी के पूर्व सरपंच तथा प्रधान प्रतिनिधि बाड़ी तथा आसपास के गांव से आये हजारों लोग उपस्थिति थे। कार्यक्रम का संचालन परिसंघ के बाड़ी ब्लाक का अध्यक्ष योगेश पालीवाल ने किया। कार्यक्रम में युवाओं ने जयभीम – जयभारत तथा डॉ. उदित राज जिन्दाबाद के अनेक नारे लगाये।

– रनजीत मीणा

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

गत 30-31 जुलाई को दिल्ली के सम्मेलन में जिन लोगों ने 28 नवंबर की रैली की सफलता के लिए सहयोग करने की जिम्मेदारी ली उनका विवरण नीचे छापा जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि स्वेच्छा से और लोग मिशन-भाव से जिम्मेदारी लें और हमें सूचित करें। इस बार इतने साथियों के साथ 28 नवंबर की रैली में शिरकत करें कि रामलीला मैदान में खड़े होने की जगह न बचे और सरकारें व शासन-प्रसाशन हमारी मागें मानने के लिए मजबूर हो जाएं। इनमें से ज्यादातर वे लोग हैं जो पदाधिकारी नहीं हैं। पदाधिकारियों से तो और अधिक करने की अपेक्षा है।

क्र. संख्या	नाम	प्रदेश	मो.	किए गए वायदे
1	अजब सिंह अहिरवार	मध्य प्रदेश	9406538535	सितंबर–अक्टूबर महीने में बड़ी जन सभा कराएंगें
2	दशरथ कुमार अहिरवार	मध्य प्रदेश	7748906240	अक्टूबर में बड़ी जन सभा कराएंगें
3	बी.एन. राम	मध्य प्रदेश (भोपाल)	8005224341	बीस हजार सदस्य बनाएंगें
4	आशीष रायपुरिया	मध्य प्रदेश (ग्वालियर)	8269875470	अक्टूबर में बड़ी जन सभा कराएंगें एवं सोसल मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार
5	प्रवेश पात्रा	उड़ीसा	9438102033	परिसंघ के फेसबुक पर लाइक बढ़वाएंगें और सोसल मीडिया द्वारा परिसंघ की गतिविधियों का प्रचार–प्रसार
6	अभिराम	उड़ीसा	993705958	सदस्यता अभियान चलाएंगें
7	केशव मूर्ति	कर्नाटक (बंगलौर)	9880173601	कर्नाटक में सदस्यता अभियान तेज करेगें
8	उमा महेश	कर्नाटक	9916545568	700 सदस्य बनाएंगें
9	निहाल सिंह	हरियाणा (गुड़गांव)	9873925060	15 सदस्य बनाएंगें
10	राजेश बहोत	हरियाणा (पानीपत)	9812143181	पहले सदस्यता अभियान चलाएंगें फिर बड़ी जन सभा कराएंगें
11	अरून कुमार हंसदा	पश्चिम बंगाल	9434723571	पश्चिम बंगाल में एक हजार सदस्य बनाएंगें
12	योगेन्द्र पासवान	झारखंड (रांची)	9810988109	50 हजार सदस्य बनाएंगें
13	अनिल कुमार	झारखंड	9431373501	दो हजार सदस्य बनाएंगें
14	संजय कांबले	महाराष्ट्र	9820111665	एक हजार सदस्य बनाएंगें, अक्टूबर में बड़ी जन सभा एवं सोसल मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार
15	राजेन्दर	महाराष्ट्र (पूना)	9272446036	अगले वर्ष राष्ट्रीय सेमिनार कराएंगें
16	जगदीश विट्ठलराव	महाराष्ट्र (भंडारा)	9421812190	सोसल मीडिया और विशेषतौर से फेसबुक द्वारा प्रचार–प्रसार
17	मनीष	महाराष्ट्र (अमरावती)	9910971549	परिसंघ को कार्यालय मुहैया कराएंगें, बड़ी जन सभा और सोसल मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार
18	नीरज चक	उत्तर प्रदेश (औरैया)	9758991130	अक्टूबर में बड़ी जन सभा कराएंगें और 1300 सदस्य बनाएंगें
19	आर.के. कमल	उत्तर प्रदेश	7525014552	एक हजार सदस्य बनाएंगे और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह हमें बड़ी जन सभा कराएंगें
20	अमित कुमार पासवान	उत्तर प्रदेश (शाहजहांपुर)	9415939873	500 सदस्य बनाएंगें और नवंबर में बड़ी जन सभा कराएंगें
21	सुखदयाल अहिरवार	उत्तर प्रदेश (ललितपुर)	9425040047	ललितपुर जिले की परिसंघ की जिम्मेदारी लेना चाहेगें
22	हरिओम दिवाकर	उत्तर प्रदेश (रामपुर)	9568511926	सोसल मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार
23	प्रदीप वर्मा	उत्तर प्रदेश	9415817078	सदस्यता अभियान चलाएंगे
24	डॉ. ओम प्रकाश	बिहार	9199289409	अक्बूबर में बड़ी जन सभा कराएंगें
25	अनिल पासवान	बिहार	9771671711	व्हाट्सएप द्वारा प्रचार–प्रसार
26	डॉ. डी. नारायण	बिहार	8051520077	15 अप्रैल, 2017 को प्रदेश स्तर पर डॉ. अम्बेडकर जयंती समारोह करेगें
27	जी. श्रीनिवासन	तमिलनाडु	9444935057	सोसल मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार
28	कल्यापन	तमिलनाडु	9962127299	दो सौ सदस्य बनाएंगें
29	रवीन्द्र सिंह कटारिया	दिल्ली	9868142799	एक हजार सदस्य बनाएंगें
30	धर्म सिंह	दिल्ली	9891438733	सोसल मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार
31	मुकेश वैद्य	दिल्ली	9212212275	500 सदस्य बनाएंगें
32	सर्वेश्वर राव	आंध्र प्रदेश (हैदराबाद)	9490300481	सोसल मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार
33	दलबीर	पंजाब (मोगा)	9988782271	300 सदस्य बनाएंगें
34	राजबीर मीना	राजस्थान	9636902568	सोसल मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार

परिसंघ की दिल्ली इकाई ने टीना डाबी को बधाई दी

डॉ. उदित राज (Ex-IRS) राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के नेतृत्व में काम कर रही दिल्ली की टीम ने 15 अगस्त 2016, (Independence Day) को परिसंघ की दिल्ली इकाई के सचिव श्री सत्या नारायण के नेतृत्व में दिल्ली कार्यकरणी सदस्य व दिल्ली देहात के सदस्यों ने कुमारी टीना दाबी, IAS (2016) सिविल सर्विस टॉपर से मुलाक़ात कर बधाई दी। टीना डाबी ने दलित समाज का न केवल नाम रोशन किया। बल्कि जाति सूचक टिप्पणी करने वाले लोगों का मुंह बंद कर दिया । दलित समाज टीना दाबी जैसी होनहार बेटी पर गौरव करती है। परिसंघ के नेताओं ने पिता जसवंत डाबी व माता हिमाली कांबले को फूल–माला भेंट कर बेटी की सफलता की बधाई दी। इस अवसर पर टीना डाबी ने परिसंघ की दिल्ली यूनिट के नेता श्री सत्य नारायण को एक पत्र लिखकर दलित समाज के सभी Students को कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया । और साथ ही दलित समाज की लड़ाई लड़ने व दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए परिसंघ के नेशनल चेयरमैन डॉ. उदित राज का तहेदिल से धन्यवाद दिया। इस अवसर पर दिल्ली यूनिट के महासचिव श्री रविंदर सिंह, संगठन सचिव श्री भानु पूनिया, सचिव श्री दया राम, सदस्य श्री विकास गिल, दिल्ली देहात यूनिट की तरफ से महासचिव श्री अशोक अहलावत, वाइस प्रेसिडेंट श्री सतबीर पचेरवाल, कैप्टन श्री मुकेश कुमार, श्री फूल सिंह, श्री वीर सिंह, श्री टेक चंद, श्री मंगत राम आदि ने भेंट की ।

टीना डाबी व उनके माता–पिता के साथ दिल्ली परिसंघ के पदाधिकारी श्री सत्या नारायण एवं दया राम

– सत्या नारायाण
सचिव
अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ (दिल्ली यूनिट)
Mob : 9873988894

ओलम्पिक में हार का सामाजिक कारण

ओलम्पिक में भारत को मात्र दो ही मेडल मिल सके। यह कोई नई बात नहीं है कि हम पहले फिसड्डी नहीं रहे हैं। जब- जब ऐसा होता है समाज का सभी वर्ग सरकार की आलोचना करके आत्मसंतोष कर लेता है। सरकार में बैठे नेता एवं अधिकारी भी साहस नहीं जुटा पाते कि जवाब दें कि इसमें केवल सरकार ही दोषी नहीं है। जो लोग ज्यादा संवेदित होते हैं, क्या वह आगे आकर के खेल को बढ़ाने में कुछ योगदान देते हैं कि केवल आलोचना ही करते हैं। जिन खिलाडियों को सुविधाएं मिलती हैं तो क्या उसका सदुपयोग करते हैं? कुछ प्रतिभाएं तो इस क्षेत्र में आने से कतरा जाती हैं कि इससे आगे चलकर जीविका उपार्जन हो पायेगा कि नहीं। दलित और पिछड़ी जातियों को जाति का घाटा खेल के क्षेत्र में भी उठाना पड़ता है। ख़राब प्रदर्शन के लिए केवल सरकार को दोष देने का मतलब है कि हम उन सभी कारणों में नहीं जा पाते जिसकी वजह से यह लज्जावश स्थिति बनती है। जमैका और केन्या गरीब देश हैं और उनकी सुविधाएं भी हमारी तुलना में कम हैं फिर भी इन देशों का प्रदर्शन हमसे कई गुना बेहतर है।

ओलम्पिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली बैटमिन्टन खिलाडी पी. वी. सिंधु का, जहाँ एक तरफ जयकारा लग रहा था तो दूसरी तरफ भारी संख्या में लोग गूगल पर यह खोजने में जुटे थे कि वह किस जाति की है। जब वह कैरोलिना मारिन से फाइनल में खेल रही थी, तब लगभग 9 लाख भारतीय गूगल पर उसकी जाति कि तलाश कर रहे थे। उसके पहले शायद किसी को जाति जानने के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन जैसे ही प्री-क्वार्टरफाइनल में पहुंची वैसे ही जाति की खोज शुरु हो गयी। जब सेमीफाइनल में पहुंची तो जाति खोजने वालों की संख्या लगभग 10 गुना और बढ़ गयी। इसी तरह से साक्षी मालिक के बारे में भी गूगल सर्च किया गया कि वह किस जाति की है। जब खेल में भी इतना जातिवाद है तो उसके अच्छे परिणाम की आशा कम ही की जा सकती है। कभी दलित समाज के विनोद काम्बली ने सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट की शुरुआत की थी और शुरुआती दौर में काम्बली का प्रदर्शन सचिन की बराबरी का हुआ करता था और कुछ तो यह भी कहते हैं कि काम्बली सचिन से बेहतर खिलाड़ी थे। काम्बली शुरू में तो दिखे और बाद में क्रिकेट की दुनिया से ही गायब हो गए। हाल में एक दलित युवा खिलाड़ी प्रणव धनावड़े ने जूनियर क्रिकेट में एक बार में 1009 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया और विवाद पैदा हुआ कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन का प्रदर्शन अच्छा न होने के बावजूद उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया। बाद में पता लगा कि सचिन तेंदुलकर के बेटे का सिलेक्शन पहले हो गया था। खैर, जो भी हो इस अचंभित खिलाड़ी प्रणव का भविष्य भी उसी तरह हो सकता है जैसे कि विनोद काम्बली का हुआ। इस तरह से अनेकों उदारहण मिल जाएंगे कि खेल जगत में ख़राब प्रदर्शन का एक कारण जाति भी है।

स्कूलों में पढ़ाया जाता है श्रम की महत्ता, लेकिन होता है उसके विपरीत ही। जब शारीरिक कार्य को करने से इज्जत ही न मिले तो सभी इससे बचने की कोशिश में तो रहते ही हैं। धीरे धीरे एक संस्कृति पनपी कि जब तक मज़बूरी न हो तब तक शारीरिक काम न करना पड़े। कुछ जातियों का पेशा ऐसा है कि वह शारीरिक कार्य करने से बच नहीं सकते, क्योंकि कोई और गुजारे का सहारा नहीं है। इस वातावरण ने हमारी शारीरिक क्षमता को घटाने का काम किया है जो कि खेल में जरुरी है। इसी से सम्बंधित दूसरी मानसिकता यह है कि अगर पढ़-लिख कर स्पर्धा नहीं कर सके तो शारीरिक और गन्दा कार्य करना पड़ेगा। ऐसा न करना पड़े तो बहुत सारी प्रतिभाएं दोनों नाव की सवारी करती हैं, एक तरफ पढ़ाई-लिखाई और दूसरी तरफ खेल। दूसरे देशों में डिग्री का सम्बन्ध रोजगार और सम्मान से नहीं है तो शुरू से ही खेल खेलने वाले पूरा ध्यान लगाते हैं। दुनिया के सबसे ताक़तवर व्यक्ति अमरीका के राष्ट्रपति ओबामा की बेटियां होटल में बैरा का काम कर रही हैं। वहां सभी अपनी मेहनत का ही खाते है न कि माँ-बाप का। वहां काम चाहे शारीरिक हो या मानसिक, स्वच्छ हो या अस्वच्छ, इंसान के सामाजिक सम्मान में कोई अंतर नहीं होता। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि इंसान या जानवर जितना अपने मांसपेशी या शरीर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वह मजबूत होगा। हमारे यहाँ जब शारीरिक काम को सम्मान दिया ही नहीं जाता तो शारीरक मजबूती कहाँ से आएगी और कैसे ओलम्पिक में मेडल हासिल कर पाएंगे?

घी और दूध खाकर बलिष्ट और स्वस्थ बनने के अतिप्रचार ने भी खिलाड़ी पैदा करने में प्रभावित किया है। अगर खाना-पीना स्वयं की मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाए तो भी बेहतर हो लेकिन शाकाहार को तूल देकर हानि ही पहुंचाई गयी है। हाई प्रोटीन मटन, चिकन और अंडा में होता है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को शारीरिक क्षमता से जोड़ रखा है जबकि इससे खिलाड़ी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अमेरिका ने अश्वेतों को खेल में शामिल किया, जिससे वहां का प्रदर्शन बेहतर हुआ तो उसी तरह से भारत में भी दलित आदिवासियों को शामिल करना चाहिए। हमारा समाज व्यक्तिवादी है, जैसे ही खिलाड़ी को सफलता मिलने लगती है तो वह माया और आराम की दुनिया की तरफ बढ़ जाता है। जितना भारत सरकार खिलाडियों पर खर्च करती है वह कम नहीं है लेकिन जब लोगों में लालच हो तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार है लेकिन मात्र वही कारण है यह कहना गलत है। आखिर में जो देश आज बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे कभी तो गरीब रहे होंगे लेकिन बार-बार कारणों को गिनाया नहीं बल्कि समाधान खोजने की कोशिश की। ख़राब प्रदर्शन के बाद बार-बार यही कहा जाता है कि बेहतर करने का संकल्प लिया जाता है लेकिन स्थिति ज्यों कि त्यों रहती है। सवा सौ करोड़ का देश जब दुनिया के सामने इतना बुरा प्रदर्शन करता है, तब गुस्सा लगता है कि फैसला लिया जाये कि हम ओलम्पिक जैसे खेलो में हिस्सा न लें ताकि कम से कम नाक कटने से बचे।

- डॉ. उदित राज

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

सांसद, डॉ0 उदित राज जी ने बौद्धों को सर्टिफिकेट का मुद्दा 11 अगस्त, 2016 को लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाया

भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 20 नवंबर, 1990 को पत्र संख्या 12016/33/90-SCD (R.Cell) (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित राज्यों को लिखा था कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लोग जिन्हें आरक्षण की सुविधा मिल रही है, को बौद्ध धर्म में धर्मांतरित होने के बाद उन्हें जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाएं और उसमें धर्म के कॉलम में 'बौद्ध' और उनकी धर्मांतरण से पहले की जाति को दर्शाते हुए प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाएं। लेकिन ज्यादातर प्रदेशों ने उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया, उल्टे उ0 प्र0 के सचिव ने पत्र संख्या 933 दिनांक 26 मार्च, 2016 (छायाप्रति संलग्न) ने 'निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार' को लिखकर पुष्टि करना चाहा है कि 20 नवंबर, 1990 को जारी सर्कुलर अभी भी वैध है या नहीं। देश के विभिन्न राज्यों में भारी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है और उन्हें आरक्षण की सुविधा पूर्ववत् मिलती रहनी चाहिए लेकिन जब वे जाति प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर धर्म के कॉलम में हिन्दू धर्म ही लिखना पड़ता हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे देश के सभी राज्यों को इस संदर्भ में नए शिरे से दिशानिर्देश जारी करवाएं।

28 नवंबर की रैली के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने हेतु परिसंघ का ऐप डाउनलोड करें

गत् 30–31 जुलाई को मावलंकर हॉल दिल्ली में आयोजित अनसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के सम्मेलन में तय किया गया था कि आंदोलन की गतिविधियां पूरे देश में प्रचारित करने हेतु सोसल मीडिया का प्रयोग सभी अनिवार्य रूप से करेगें और परिसंघ का ऐप भी डाउनलोड करके इसे इस्तेमाल करेगें लेकिन सोसल मीडिया का उपयोग बहुत ही कम लोगों ने शुरू किया है। परिसंघ का ऐप भी बार–बार एस. एम.एस. द्वारा सूचित करने के बाद भी अभी तक लगभग 500 लोगों ने ही डाउनलोड किया है। सभी साथियों से अपील है कि रैली से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और गतिविधियों को तेज करने में सोसल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें और परिसंघ का ऐप https://goo.gl/qNfYK9 लिंक से डाउनलोड करें या डाउनलोड लिंक प्राप्त करने के लिए 011–66978003 पर मिसकाल करें। किसी प्रकार की समस्या हो तो कार्यालय में सुमित – 9868978306 से सम्पर्क करें।

– डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष

You keep the cow's tail

Anand Patwardhan

The march that reached Una on August 15 marked the most significant Independence Day I have ever witnessed. Mainstream media, barring exceptions, paid scant heed, focusing instead on the prime minister's usual sabre-rattling. Headlines gleefully reported that Narendra Modi had laid down the gauntlet against Pakistan. You mess with Kashmir and we will mess with Balochistan, he declared, tacitly admitting a democratic failure in both countries.

What transpired at Una was dramatically different. The trigger was last month's public parading and flogging of Dalit youth who had been skinning a dead cow. The "cow protectors" recorded and circulated their feat on social media. As the clip went viral, Dalits were shocked into action.

Gujarat has often seen anti-Dalit atrocities with the police displaying its upper caste bias. By 2002, a new right-wing strategy emerged. Dalits were recruited as foot-soldiers to attack Muslims. In the next decade, as the RSS aspired to capture national power, Ambedkar began to appear on BJP banners and an alliance with Dalits appeared possible. But while Ambedkar's icon was desirable, not so his egalitarian vision and deep distaste for misogynist Hindu shastras. Predictably, caste violence increased in proportion to Dalit assertion. In 2012 at Thangadh, the police used AK 47s to kill three unarmed Dalit protesters. With Modi as PM, cow vigilantes and Hindutva militants were further emboldened.

With seven per cent Dalits in Gujarat, mass mobilisation has never been easy. Valiant leaders like Valjibhai Patel are in their 80s, while sops and inertia have robbed the community of effective elders. It is in this vacuum that a young Dalit like Jignesh Mevani emerged. He and other youth leaders like the Parmars, Suresh Aadya and Advocate Shamshad Pathan have given shape to the spontaneous uprising after Una. This potent mix of young Dalits and Muslims also has the invaluable support of people like Rahul Sharma, one of the bravest IPS police officers who tried to stem the Gujarat riots of 2002, only to face innumerable obstacles ever since.

Support poured in from across the country. The ambitious route covered 400 kilometers in 10 days, partly on foot and partly in assorted vehicles, stopping before every town so people could proceed on foot to be greeted by a welcoming party from the approaching town. Fed and refreshed they set off, again on foot towards the next town, accompanied for a part of the journey by their recent hosts.

The support base kept growing until the caravan reached the outskirts of Una on August 14. Here, they faced the first signs of upper caste resistance. Near Samter, where the Dalit youth had first been assaulted, the OBC Durbar community staged a road block. The marchers avoided confrontation and took a detour to reach Una by the 14th afternoon. The previous night, Grishma of Dalit Camera had gone to Samter village after hearing about their aggression. She

barely managed to get back with her equipment intact. The next day she went again with a young reporter to interview Durbar men when they suddenly went on the offensive. As the reporters were escaping on a motorbike, a car deliberately chased and knocked them down and then sped off. Both suffered injuries, but bandaged and bleeding, were back on the job that very night.

On the 15th, Una rang with cries of "Jai Bhim" as people arrived in droves. We stopped at an Ambedkar statue where, under a tent, a large family was sitting on a hunger strike. We heard the heartrending tale of the Sarvaiyya family. They were the only Dalits in a Koli (OBC) village and owned 15 acres of irrigated land. Four years ago, young Lalji Sarvaiyya was burnt alive in his hut by a mob that suspected he had eloped with a Koli girl. The Sarvaiyyas are now jobless and homeless as promises to grant them an alternate plot have not materialised.

By now, despite roadblocks and stone pelting, 20,000 had reached Una. Apart from local Dalits, there were Rohith Vemula's mother and brother, Dontha Prashanth of Ambedkar Students Association and many more from all castes and creeds representing various shades of the politics of reason. Speeches from the stage were limited as getting home safely was a priority that could be ensured only if the meeting concluded early.

On August 15, as the tricolour unfurled in the presence of Radhika Vemula and other affected Dalit families, the Jana Gana Mana was sung by thousands of voices that this country has rarely been interested in hearing. Jignesh called out: "You can keep the cow's tail. But give us our land!" An oath was administered: "We vow not to enter your sewers and not to skin your dead cattle."

The government was given 30 days to grant every Dalit family five acres of land, failing which a rail roko would be launched. Jignesh's speech was followed by JNU's Kanhaiya Kumar who had come to Una despite running a high fever (later diagnosed as malaria). His speech was short and ended with the now famous chant demanding azadi from Brahminism, casteism, capitalism, and fascism.

Babu Sarvaiiya, father of the boys beaten at Una, spoke about the terror being unleashed in the countryside. Radhika Vemula spoke of how after Rohith's death, her new family consists of oppressed Dalits everywhere.

The meeting concluded at noon but the day had not ended. A backlash was underway. On the Samter side of the bridge leading out of Una, Durbar youth were stopping vehicles and beating up presumed Dalits. Ambulances screamed up and down the road. On the Una side, Dalit supporters began creating their own roadblock. The police concentrated on persuading Dalits not to indulge in violence. The situation was volatile. As tempers soared, organisers reminded people that Ambedkar had never resorted to violence.

The Gir Somnath police chief ingenuously assured us that arrests of Durbars would be done as soon as law and order was restored. Jignesh's presence meant that Dalits would keep gathering around him so it was decided that he should return to Ahmedabad through alternate routes. We stayed back with cameras to keep the pressure on the police to ensure the safety of the protesters. We visited a government hospital in Una where four injured Dalit boys had been brought in. Their motorcycles were destroyed. One had a brother missing. They recognised their Durbar attackers. A Dalit was brought in with a bullet injury in his leg. We went back to the police station to ask them to file FIRs. Again we were assured that this would be done "once law and order was restored".

The police finally cleared the road to Samter, resorting to firing in the air. We left town that night and heard of no further major incidents.

The positive impact has been huge but criticism exists that local Dalits bore the brunt. Yet when we talked to the injured in Una, they were very proud to have helped end the silence. Landless Dalits forever forced to do jobs no one else would do have demanded both respect and land.

Dead cows now litter many villages of Gujarat — a lesson for the whole country.

- Patwardhan is a documentary filmmaker

- Courtesy: Indian Express (August 26, 2016)

Tamil Nadu State Convention to be held on 17th Sep.

The Tamil Nadu State Convention of the All India Confederation of SC/ST Organizations will be held on Saturday, 17th September 2016 in the presence of Dr. Udit Raj, National Chairman of the Confederation, to fight for our Constitutional rights such as reservation in promotion, reservation in private sector, condemning SC/ST atrocities, filling up backlog vacancies and to honor SC/ST movement leader with the Dr. Ambedkar Award. All Confederation leaders, office bearers, members of the Confederation from Tamil Nadu and nearby states, as well as dedicated missionaries are requested to attend the Convention from 9 AM to 4 PM on 17th September 2016 at Faiz Mahal A/c Hotel Imperial Complex, Near Albert Theatre, Egmore, Chennai 600 008.

S. Karuppaiah
Tamil Nadu State President
All India Confederation of SC/ST Organizations
098946 18322, skpmfl@rediffmail.com

Five-year plan junked, fate of Dalit sub-plans worries MP

NEW DELHI: As the Modi government consigns five-year plans to history, BJP's prize Dalit catch and Rajya Sabha MP Narendra Jadhav has warned that it would pose an existential threat to the Dalit sub-plan - mandatory budgetary allocation to feed schemes for welfare of Scheduled Castes (SCs).

"I don't know what will happen to Scheduled Caste Sub Plan (SCSP). If there is no 13th five-year plan... there may be no Scheduled Caste Sub-Plan Tribal Sub-Plan," Jadhav told TOI. "I certainly do (see a threat to SCSP). This is the most important component which deals with the underprivileged," Jadhav said.

SCSPTSP mandates that every central ministry or department will allocate budget for SCST welfare in proportion to their population. They are mentioned in detail in every plan paper to ensure they guide the budgetary process.

A Planning Commission member under the UPA, Jadhav was picked by BJP to be part of Ambedkar's 125th birth anniversary celebrations committee before being sent to Rajya Sabha as a nominated MP.

The 12th plan will end in 2017 and the government has said it would not come out with another five-year plan but would replace it with a 15-year vision document and three-year action plan.

Asked if the twin sub-plans could not exist as part of annual ministerial budgets which would continue even in the changed system, Jadhav said, "It was not happening even when SCSP existed. So, what will happen when it is not there? Moral pressure will not be there as it did under five-year plan."

The sub-plans came into being in the 1970s but their implementation remained poor. The sub-plans were said to be impractical since most central departments were executing projects like roads, schools and in frastructure, which catered to all, irrespective of caste.

As Planning Commission member, Jadhav had revised the guidelines to exempt some ministries from SCSPTSP to make the system workable. He said allocations under subplans did not cross 9.50% which was way short of the population share of Dalits and tribals. "In the last three years, there has been no improvement in the earmarking and actual expenditure under sub-plans. I showed it in my maiden speech in Rajya Sabha," he added.

The RS MP said the gap in socio-economic indicators of Dalits and other communities had narrowed a bit but was still very high. "Effective implementation of SCSP and TSP will go a long way in solving the problems faced by underprivileged communities," he said.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Five-year-plan-junked-fate-of-Dalit-sub-plans-worries-MP/articleshow/53866146.cms

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 19 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 August, 2016

Social causes responsible for our loss at the Olympics

In the Rio Olympics, India could win only 2 medals. This is not a new phenomenon for us. Whenever some thing of this kind occurs, all parts of societies discuss failure of the Government and are satisfied. The Government and the bureaucracy generally do not have the courage to say openly that this is not just the Government's responsibility. Those who profess themselves to be outraged; are they ready to come forward and do something for sports in India, or will they be satisfied only with discussions? The sportspersons who are given facilities - are they able to utilise them properly? There are many people afraid to enter the arena of sports because there is no guarantee of livelihood down the line. Dalits and backwards face exclusion even in the field of sports. When we blame the Government for our failure in sports, we are unable to enter into the real reasons for our shameful performance. Jamaica and Kenya are countries much smaller than ours, and facilities there are also worse than ours, yet they do much better in Olympics than us.

While Olympic silver medallist P V Sindhu was being celebrated throughout the country, many people were trying to find out her caste. When she was playing Carolina Marin in the finals, around 9 lac Indians were googling to find her caste. Before that, no one was interested in knowing her caste, but as soon as she reached the pre-quarterfinals, her caste became a hot topic of curiosity. When she reached the semifinals, the number of people searching for her caste increased almost 10 times. Similarly, people also started googling to find out Sakshi Malik's caste. When there is so much casteism in sports, then good results are unlikely to be seen. A Dalit, Vinod Kambli had started playing cricket with Sachin Tendulkar, and at the start, there performance levels were equal; some had also said that Kambli was perhaps a better player than Tendulkar. Kambli was a regular in the beginning, but later he disappeared altogether. Recently, at the junior level, a Dalit player Pranav Dhanawade scored an unbeaten 1009 runs in an innings; yet he was dropped from the team leading to a major controversy, while Sachin's son Arjun Tendulkar was selected despite his comparatively poorer performance. Later it was found out that Arjun had been selected much earlier. We can find many similar instances proving that the caste system is responsible for our poor performance in sports.

We are taught the importance of hard work in schools, but reality is much different. Since manual labor is not at all respected in our country, most people try to escape from this. Slowly, a system has developed where people are not interested in physical labor, unless it becomes necessary. Some castes cannot escape physical labor since that is still their only source of livelihood. This system has lead to a weakening of our physical prowess, which is necessary for sports. Another corollary of this is that unless one is educated, they will be doomed to a life of physical labor. In other countries, education is not related to employment and status, so people start playing from childhood. Daughters of the world's most powerful man, President Obama are working as waiters. There everyone is responsible for their own lives, there is no concept of ancestral property and being dependant on parents. There whether one's work be physical or intellectual, clean or unclean, there is no effect on social status and standing. When in our country, there is no respect of physical labor, why would one develop physical prowess and without that, there is no chance of winning in Olympics.

The tradition of ghee and milk being a large part of our diet has also contributed to the development of sports. If our diet was independent of external influences, then perhaps the concept of vegetarianism would not have harmed our physical growth - we are denied a high protein diet of chicken, mutton and eggs. The performance of the United States in sports improved after blacks were brought into the mainstream; similarly, in India Dalits and backwards must also be brought into the mainstream. Our society is selfish, as soon as a player achieves some success, he is lured into a life of comfort and security. The amount spent by the Government on sports is not small, but what can the Government do when people are greedy and selfish? There is corruption in our system, but that alone is not responsible for our poor performance. The countries which are doing well in sports today must have been poor once, but it is better to look for solutions instead of playing the blame game. After our poor performance, many pledges are taken to do better next time, but the situation remains the same. When a country of 125 crore people performs so poorly in the Olympics, then it is felt that it is better that the country not participate in such events - at least then such a poor performance will not be seen on the world stage.

- Dr. Udit Raj

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya